रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एच० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 30 मार्च, 1998/9 चैत्र, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 30 मार्च, 1998

संख्या 1-19/98-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्यांक 1)

1250—राजपत्र/98-30-3-98—1,278. (1305) मूल्य : 1 रुपया।

जो दिनांक 30 मार्च, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

अजय भण्डारी,
सचिव ।

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

1998 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998

31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1998 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए 5,87,44,69,811 रुपये की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां जिनका योग 5,87,44,69,811 रुपये (पांच अरब, सतासी करोड़, चवालीस लाख, उनहत्तर हजार, आठ सौ ग्यारह रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1997-98 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	5,52,15,031	1,10,216	5,53,25,247
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	1,06,80,000	29,30,000	1,36,10,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	6,32,04,000	1,47,23,911	7,79,27,911
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	34,18,46,000	51,331	34,18,97,331
		(पूंजी)	18,86,000	—	18,86,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	10,02,19,000	—	10,02,19,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	1,64,35,000	—	1,64,35,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	13,48,81,436	—	13,48,81,436
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	37,45,23,000	42,63,360	37,87,86,360
		(पूंजी)	5,13,00,000	—	5,13,00,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	30,49,91,000	3,32,934	30,53,23,934
		(पूंजी)	2,17,53,000	17,66,353	2,35,19,353
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	4,05,32,000	—	4,05,32,000
		(पूंजी)	5,74,87,000	—	5,74,87,000
11	कृषि	(राजस्व)	22,16,39,400	—	22,16,39,400
		(पूंजी)	6,47,36,000	13,218	6,47,49,218
12	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	4,73,95,000	—	4,73,95,000
		(पूंजी)	14,40,85,000	5,83,022	14,46,68,022
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	3,36,67,000	—	3,36,67,000
		(पूंजी)	4,34,000	—	4,34,000
14	पशुपालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	7,59,34,299	73,045	7,60,07,344
15	मत्स्य	(राजस्व)	5,99,000	—	5,99,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	2,97,84,000	1,49,392	2,99,33,392
		(पूंजी)	58,90,000	—	58,90,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	13,35,14,000	—	13,35,14,000
		(पूंजी)	11,26,62,000	—	11,26,62,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	23,44,53,500	5,81,208	23,50,34,708
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	2,41,67,415	10,000	2,41,77,415
		(पूंजी)	1,13,69,000	—	1,13,69,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	17,39,99,000	—	17,39,99,000
21	सहकारिता	(पूंजी)	3,95,16,000	—	3,95,16,000
22	खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व)	5,48,79,000	—	5,48,79,000
		(पूंजी)	3,37,14,000	—	3,37,14,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	7,00,000	—	7,00,000
		(पूंजी)	1,68,67,00,000	—	1,68,67,00,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण	(राजस्व)	25,17,057	5,51,945	30,69,002
25	सड़क, जल परिवहन और नागर विमानन	(राजस्व)	31,30,06,000	—	31,30,06,000
		(पूंजी)	1,24,66,000	—	1,24,66,000
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन	(राजस्व)	4,62,72,380	—	4,62,72,380
		(पूंजी)	2,81,21,000	55,29,000	3,36,50,000
27	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	1,09,26,000	—	1,09,26,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	39,48,54,860	—	39,48,54,860
		(पूंजी)	25,91,87,000	—	25,91,87,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	20,00,000	—	20,00,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	3,55,16,617	18,881	3,55,35,498
		(पूंजी)	3,31,25,000	—	3,31,25,000
	कुल जोड़		5,84,27,81,995	3,16,87,816	5,87,44,69,811
		(राजस्व)	3,27,63,50,995	2,37,96,223	3,30,01,47,218
		(पूंजी)	2,56,64,31,000	78,91,593	2,57,43,22,593

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
30 मार्च, 1998.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल संख्या वित्त-ए-सी (2)-20/97]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998

31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक** ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
30 मार्च, 1998.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Bill No. 1 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1998

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 1998.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1998.

Issue of a further sum of Rs. 5,87,44,69,811 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year, 1997-98.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 5,87,44,69,811 (Five hundred eighty seven crores, forty four lakhs, sixty nine thousand, eight hundred and eleven rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year, 1997-98 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
De-mand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Conso-lidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	5,52,15,031	1,10,216	5,53,25,247
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	1,06,80,000	29,30,000	1,36,10,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	6,32,04,000	1,47,23,911	7,79,27,911
4	General Administration	(Revenue)	34,18,46,000	51,331	34,18,97,331
		(Capital)	18,86,000	—	18,86,000
5	Land Revenue	(Revenue)	10,02,19,000	—	10,02,19,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	1,64,35,000	—	1,64,35,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	13,48,81,436	—	13,48,81,436
8	Education, Sports, Arts and Culture	(Revenue)	37,45,23,000	42,63,360	37,87,86,360
		(Capital)	5,13,00,000	—	5,13,00,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	30,49,91,000	3,32,934	30,53,23,934
		(Capital)	2,17,53,000	17,66,353	2,35,19,353
10	Public Works	(Revenue)	4,05,32,000	—	4,05,32,000
		(Capital)	5,74,87,000	—	5,74,87,000
11	Agriculture	(Revenue)	22,16,39,400	—	22,16,39,400
		(Capital)	6,47,36,000	13,218	6,47,49,218
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	4,73,95,000	—	4,73,95,000
		(Capital)	14,40,85,000	5,83,022	14,46,68,022
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	3,36,67,000	—	3,36,67,000
		(Capital)	4,34,000	—	4,34,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	7,59,34,299	73,045	7,60,07,344
15	Fisheries	(Revenue)	5,99,000	—	5,99,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	2,97,84,000	1,49,392	2,99,33,392
		(Capital)	58,90,000	—	58,90,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	13,35,14,000	—	13,35,14,000
		(Capital)	11,26,62,000	—	11,26,62,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	23,44,53,500	5,81,208	23,50,34,708
19	Social Security and Welfare (Including Nutrition)	(Revenue)	2,41,67,415	10,000	2,41,77,415
		(Capital)	1,13,69,000	—	1,13,69,000
20	Rural Development	(Revenue)	17,39,99,000	—	17,39,99,000
21	Co-operation	(Capital)	3,95,16,000	—	3,95,16,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	5,48,79,000	—	5,48,79,000
		(Capital)	3,37,14,000	—	3,37,14,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Water and Power Development	(Revenue)	7,00,000	—	7,00,000
		(Capital)	1,68,67,00,000	—	1,68,67,00,000
24	Stationery and Printing	(Revenue)	25,17,057	5,51,945	30,69,002
25	Road, Water Transport and Civil Aviation	(Revenue)	31,30,06,000	—	31,30,06,000
		(Capital)	1,24,66,000	—	1,24,66,000
26	Tourism and Hospitality Organisation	(Revenue)	4,62,72,380	—	4,62,72,380
		(Capital)	2,81,21,000	55,29,000	3,36,50,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	1,09,26,000	—	1,09,26,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	39,48,54,860	—	39,48,54,860
		(Capital)	25,91,87,000	—	25,91,87,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	20,00,000	—	20,00,000
31	Tribal Development	(Revenue)	3,55,16,617	18,881	3,55,35,498
		(Capital)	3,31,25,000	—	3,31,25,000
		Grand Total	5,84,27,81,995	3,16,87,816	5,87,44,69,811
		(Revenue)	3,27,63,50,995	2,37,96,223	3,30,01,47,219
		(Capital)	2,56,64,31,000	78,91,593	2,57,43,22,593

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year, 1997-98.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 30th March, 1998.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A-C(2)20/97]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1998 recommends, under article 207 of the Constitution of India the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1998

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 1998.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SURIENDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The 30th March, 1998.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।